



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या Appeal / File No	मूल आदेश सं / O.O. No.	दिनांक / Date
	V2/284/RAJ/2016	147/ST/REF/2016	11.11.2016

*661 से 682
132 & 133*

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-147-2017-18

आदेश का दिनांक /
Date of Order: **26.12.2017** जारी करने की तारीख /
Date of issue: **27.12.2017**

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर, राजकोट / जम्नगर / गण्डिधाम; द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सूचित /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellants & Respondent :-**
M/s. Kunal Structure (India) Pvt. Ltd., Kunal House Ganga Park, Plot No. 10, Opp. Sanskruti Apartment,Panchvati Road, Rajkot - 360 001

इस आदेश(अपील) से अवगत कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से उपयुक्त अधिकारी / अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण सूचकांक से सम्बन्धित सभी मामलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जाती चाहिए। /
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बसाए गए अपील के अलावा शेष सभी अपील सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण (विस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहामनी भवन अलाहा अहमदाबाद- 360016 को की जाती चाहिए। /
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumai Bhawan, Asarwa Ahmedabad-360016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित निम्न रूप पर EA-3 को धार प्रतियों में दर्ज किया जाता चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की सीमा धारा की सीमा और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भ्रतान, संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा या सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सर्वजिम्मेदार शेर के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भ्रतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। न्यूनतम आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवंटन-पर के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के अंतर्गत निर्धारित रूप पर S.T.5 में धार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिन आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होती चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की सीमा धारा की सीमा और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भ्रतान, संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सर्वजिम्मेदार शेर के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भ्रतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। न्यूनतम आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवंटन-पर के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) विल अपीलियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दायें की गयी अपील, सेवान्तर नियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-7 में की जा सकने वाली एवं उसके साथ आवृत्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अध्याय आवृत्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पठित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें (जहाँ से एक प्रति प्रामाणिक होनी चाहिए) और आवृत्त द्वारा सहायक आवृत्त अध्याय उपयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवान्तर, से अपील न्यायाधिकरण को आवेदन दाने करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवान्तर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टैट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की विलियम अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवान्तर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्कसेवा कर मात्र के 10 प्रतिशत (10%), जब मात्र एवं जुरमान विवादित है, या जुरमान, जब केवल जुरमान विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जहाँ कि जहाँ वाली अपीलें टैक्स रॉडिंग सेवा से अपील न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवान्तर के अंतर्गत 'आवृत्त या शुल्क' में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- (ii) सेवान्तर जहाँ की जी गैरु गलत रॉडिंग
- (iii) सेवान्तर जहाँ नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत टैक्स

- बशर्त कि इस धारा के प्रावधान विलियम (सं. 2) अधिनियम 2014 के अंतर्गत से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष विचारणीय प्रकरण नहीं एवं अपील को लागू नहीं होगी।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, 'Duty Demanded' shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Central Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Central Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षण प्राधिकार विभागाधीन मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के फटन पराल के अंतर्गत जहाँ विलियम, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, विलियम अंतर्गत, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जेवान्तर दीप भवन, सस्ट भवन, नई दिल्ली-110001, को किया जाता चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section 35B ibid.

(i) यदि भारत के किसी भूकाल के मामले में, जहाँ भूकाल किसी भारत को किसी करखाने से अंतर गुरु के परामत्र के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंतर गुरु से दूसरे अंतर गुरु परामत्र के दौरान, या किसी अंतर गुरु में या अंतरण में भारत के परामत्र के दौरान, किसी करखाने या किसी अंतर गुरु में भारत के भूकाल के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे मात्र के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे मात्र पर लगी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के फूट (रिबैट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किया बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को मात्र निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इप्टी केबल इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत समय की गई है और ऐसे आदेश जो आवृत्त (अपील) के द्वारा विलियम अधिनियम (सं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तरीक अन्तः सहायक पर या बट से पठित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां फॉर्म संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संकेतन के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अद्ययगी के साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अद्ययगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त टन से किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी की निम्न पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) पञ्चासपंचित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं अन्तर्गत आदेश की प्रति या निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट अलग होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवान्तर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में उचित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान जाना चाहिए। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकरण को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलकर्ता विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in की टैब सलने हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

94

:: ORDER IN APPEAL ::

M/s. Kunal Structure (India) Pvt Ltd, Kunal House, Ganga Park, Plot No.10, Opp. Sanskruti Apartment, Panchvati Road, Rajkot-360001 (*hereinafter referred to as "the Appellant"*) has filed present appeal against Order-in-Original No. 147/ST/REF/2016 dated 11.11.2016 (*hereinafter referred to as "the impugned order"*), passed by the Assistant Commissioner, Service Tax Division, Rajkot (*hereinafter referred to as the "lower adjudicating authority"*).

2. Briefly stated, facts of the case are that appellant had filed refund claim of interest of Rs. 60,17,196/- in terms of Section 101 of the Finance Act, 2016. The lower adjudicating authority vide impugned order rejected refund claim being interest paid for late payment of service tax at the material time and Section 101 of Finance Act, 2016 deals with refund of service tax paid and not for interest paid.

3. Being aggrieved with the impugned order, appellant has filed appeal, *inter-alia*, on the following grounds: -

(i) As per Sr No. 12 of the Notification 25/2012-ST dated 20.06.2012 there was confusion prevailing over the status of M/s. Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd (*hereinafter referred to as M/s.SSNNL*) and the appellants paid the service tax along with interest for the services provided to M/s. SSNNL during the period from 01.07.2012 to 29.01.2014. The lower adjudicating authority has erred in interpreting Section 101 of Finance Act, 2016. Section 11B of Central Excise Act, 1944(*hereinafter referred to as the Act*) is a relevant section for claiming refund of duty/tax as well as interest, if any, paid on such duty/tax. Hence, from the above, it is adequately clear that interest paid, on late payment of service tax in relation to which refund claim had been filed, is eligible to be refunded as service tax on which an interest has been deposited, has been made exempt retrospectively vide Section 101 of Finance Act, 2016.

(ii) Interest is not a duty or tax and, it is an amount levied on account of delayed payment of tax and such interest is eventually based on the tax liability paid late. Now, when the tax itself has been exempt retrospectively the question of payment of interest does not arise on such exempted tax and the appellant should be granted refund of interest paid by them. The appellant relied on decisions in the case of *Motherson Sumi System Ltd.* reported as 2007 (208) ELT

[Signature]

209 (Tri. – Delhi) and Gemini Steel Tubes Ltd. reported as 2006 (194) ELT 88 (Tri. – Bang.) .

4. Personal hearing in the matter was attended to by S/Shri Bishan R Shah, Chartered Accountant and Shri Pradeep Mishra, CFO of the Appellant who reiterated the Grounds of Appeal and submitted that Section 11B talks of refund of duty and interest; that being law abiding assessee, they have paid service tax and interest on delayed payment of Service tax; that now no service tax is payable due to Section 101 of the Finance Act, 2016, hence no interest is payable and hence as per case laws interest paid by them should also be refunded to them; that they would submit written submission within 7 days. Appellant in their written submission dated 24.11.2017 contended that as per the provisions of Section 11B of the Central Excise Act, 1944 made applicable to Service Tax, interest paid by them should be refunded to them.

FINDINGS: -

5. I have carefully gone through the facts of the case, impugned order, appeal memorandum and written as well as oral submissions made by the appellant. The issue to be decided is whether in the facts and circumstances of the present case, the impugned order passed by the lower adjudicating authority rejecting claim for refund of interest paid for late payment of service tax due to retrospective exemption vide Section 101 of Finance Act, 2016, is correct or not.

6. I find that the lower adjudicating authority vide impugned order rejected refund claim of Rs. 60,17,196/- being interest paid for late payment of service tax by the Appellant on the ground that service tax was to be paid in time by the Appellant but not paid in time and Section 101 of Finance Act, 2016 deals with refund of service tax and not refund of interest. The appellant has contended that when service tax has been exempted retrospectively, the question of payment of interest does not arise on such exempted service tax and the appellant should be granted refund of interest amount. I find that Central Government has granted retrospective exemption from payment of service tax in respect of taxable services provided to certain government authority or a board etc. for construction of canal, dam, etc. under Section 101 of the Finance Act, 2016, which reads as under: -

“SECTION 101. Special provision for exemption in certain cases relating to construction of canal, dam, etc. — (1) Notwithstanding anything contained in section 66B, no service tax

shall be levied or collected during the period commencing from the 1st day of July, 2012 and ending with the 29th day of January, 2014 (both days inclusive) in respect of taxable services provided to an authority or a board or any other body —

- (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
- (ii) established by the Government,

with ninety per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a municipality under article 243W of the Constitution, by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation or alteration of canal, dam or other irrigation works.

(2) Refund shall be made of all such service tax which has been collected but which would not have been so collected had sub-section (1) been in force at all material times.

(3) Notwithstanding anything contained in this Chapter, an application for the claim of refund of service tax shall be made within a period of six months from the date on which the Finance Bill, 2016 receives the assent of the President.

(Emphasis supplied)

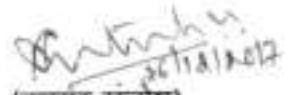
7. It could be seen that Section 101(1) of Finance Act, 2016 grants retrospective exemption in respect of taxable services provided during the period from 01.07.2012 to 29.01.2014 to a government / local government authority or a board or any other body set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or established by the Government; Section 101(2) of the Act states that refund shall be made of all such service tax which has been collected but which would not have been so collected had Section 101 (2) been in force at all material time. In the instant case, the appellant had paid service tax on taxable services provided to M/s. SSNNL by them during the said exempted period and had collected it from the service receiver. I find that the service receiver had paid the amount of Service Tax to the Appellant as per their business terms and conditions. In these circumstances all liabilities lie with the service recipient to fulfill the obligations between them and the Appellant. Once, service recipient pays the amount of service tax to the Appellant, question of refund of service tax by department does not arise and since no refund of service tax arises, no liability lies with the department in terms of Section 101 of the Finance Act, 2016 to refund Service Tax or Interest on Service Tax paid by the Appellant due to late payment of Service Tax at the material time. I find that the appellant had paid interest amount as they had failed to deposit service tax in Government account within stipulated time limit at the material time. I also find that the statutory provisions

exempt levy of service tax retrospectively for the service tax collected and not interest on such tax. Hence, I hold that the appellant is not entitled for refund of interest or late fee, if paid. Therefore, the impugned order rejecting refund of interest is correct, legal and proper.

8. In view of above, I uphold the impugned order and reject the appeal filed by the appellant.

९. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.


(कुमार संतोष)
आयुक्त (अपील्स)

By Regd. Post AD

To,

M/s. Kunal Structure (indi) Pvt Ltd,
Kunal House, Ganga Park,
Plot No.10, Opp. Sanskruti Apartment,
Panchvati Road, Rajkot-360001

मे. कुनाल स्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा लिमिटेड
कुणाल हाउस, गंगा पार्क
प्लॉट नं १०, संस्कृति अपार्टमेंट, पंचवटी रोड
राजकोट ३६०००१

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, GST & Central Excise Commissionerate, Rajkot.
- 3) The Assistant Commissioner, GST & Central Excise Division-I, Rajkot.
- 4) Guard File.